भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 466
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हीट एक्शन प्लान (एचएपी)

†466. श्री एन.रेड्डप्पः

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश हीट एक्शन प्लान (एचएपी) में कमजोर एवं असुरक्षित लोगों के बारे में सही आकलन नहीं किया जाता है जिसके कारण इस प्रकार की आबादी की पहचान से संबंधित आंकड़े नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास उक्त प्लान के तहत सही आकलन करने हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसके मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एचएपी में निर्धारित कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की जांच हेतु कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की वर्तमान में राज्यों में एचएपी के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय आबंटन प्रदान करने की कोई योजना है क्योंकि कई योजनाओं में वित्तपोषण स्त्रोतों पर चर्चा नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क)-(ग) विभिन्न मौसमी आपदा घटनाओं के लिए प्रभाव-आधारित पूर्व चेतावनी सेवाएं प्रदान करने के अंग के रूप में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जान-माल की हानि, क्षति या अन्य स्वास्थ्य हानि, संपत्ति क्षति, रोजी-रोटी एवं सेवाओं की हानि करने वाले तेरह सबसे जोखिमकारी मौसमी घटनाओं समेत लू के लिए एक भारतीय जलवायु जोखिम एवं सुभेद्यशीलता एटलस तैयार किया है। यह वेब एटलस जियोग्राफिक इंफॉरमेशन सिस्टम (GIS) टूल्स का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है, तथा यह भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पुणे की वेबसाइट (https://www.imdpune.gov.in/hazardatlas/index.html) पर उपलब्ध है। इस एटलस में सभी कैलेंडर महीनों और वार्षिक पैमाने पर जोखिम वाली घटनाओं और सुभेद्यता संबंधी जिलों के नक्शे प्रदान किए गए हैं। ये हैजर्ड मैप जलवायु डेटा, जनसंख्या जनगणना डेटा तथा हाउसिंग डेंसिटी पर आधारित हैं, तथा इन्हें बनाने में विभिन्न सांख्यिकीय एवं गणितीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जलवायु सुभेद्यशीलता मैप भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के "वार्षिक आपदा जलवायु रिपोर्ट" के वार्षिक प्रकाशन से लिए गए आपदा आंकड़े के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनके कारण जान-माल की हानि होती है।

यह पाया गया कि अधिकांश पीड़ित कृषि श्रमिक, तटीय समुदाय के निवासी और गरीबी स्तर (बीपीएल) श्रेणी से नीचे रहने वाले थे, जो ज्यादातर घर के बाहर वाले काम-काज में थे। इन तेरह जलवायु जोखिमों में से ग्यारह जोखिमों के लिए सामान्यीकृत सुभेद्यशीलता सूचकांक पर आधारित सुभेद्यशीलता पैमानों की विभिन्न श्रेणियों में आपदाकारी मौसमी घटनाओं द्वारा प्रभावित जिलों एवं जनसंख्या का प्रतिशत तैयार किया गया है। लू का सुभेद्यशीलता एटलस दर्शाता है कि 13 प्रतिशत जिले और 15 प्रतिशत जनसंख्या मध्यम से लेकर काफी उच्च रूप से सुभेद्यशील हैं, तथा 4 प्रतिशत जिले और 7 प्रतिशत जनसंख्या काफी उच्च रूप से सुभेद्यशील हैं। राजस्थान (15 जिले) और आंध्र प्रदेश (13 जिले) राज्य लू के प्रति सबसे अधिक सुभेद्यशील हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने निगरानी तथा समयोचित पूर्व पूर्व चेतावनी में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे जान-माल की हानि कम करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में हीट एक्शन प्लान (HAPs) शुरू किया है, ताकि लू के बारे में पूर्व चेतावनी दी जा सके और साथ ही ऐसी स्थितियों के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परामर्श दिया जा सके। अभी तक 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAPs) कार्यान्वित किए गए हैं, जहां उच्च तापमान के कारण लू की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लू बुलेटिन प्रतिदिन भारतीय समय के अनुसार सायं 4 बजे जारी की जाती है, जिसमें अगले 5 दिनों के दौरान लू संबंधी पूर्वानुमान एवं चेतावनियां बतायी जाती हैं। NDMA दिशानिर्देशों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में लू कारण होने वाले अपेक्षित प्रभाव को कलर कोड (हरा, पीला, नारंगी, तथा लाल) में दिखाया जाता है, तथा विशिष्ट प्रभाव को टेक्स्ट में वर्णित किया जाता है। मौसम केंद्र / प्रादेशिक मौसम केंद्र द्वारा जिला स्तरों पर बुलेटिन जारी किए जाते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौजूदा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा ईमेल सेवाओं के अतिरिक्त अपनी पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाओं के प्रसार हेतु विभिन्न नए प्लेटफॉर्म एवं रणनीतियां शुरु की हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हितधारकों की आसान समझ के लिए अब दैनिक एवं साप्ताहिक वीडियो मैसेज की मदद से लू संबंधी जानकारी प्रदान कर रहा है। चेतावनी संदेश प्रसारित करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया पर काफी बल दिया जाता है। लू चेतावनी सेवाओं के बारे में जिला वार एवं स्थानीयकृत सूचना प्रदान करने के लिए समर्पित राज्य वेबसाइट आरंभ की गई है। लू संबंधित क्षेत्र विशिष्ट बुलेटिन भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, ताकि वेक्टर जनित रोगों के संभावित संचार के रोकथाम की तैयारी की जा सके ताकि कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादकता की हानि बचाने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

(घ)-(ङ)जी नहीं। हीट एक्शन प्लान का कार्यान्वयन तथा इसकी प्रभावी निगरानी की जिम्मेदारी तत्संबंधी राज्य सरकारों की है।

****